INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका

डॉ. सुनीता डॉ. राजेश मारकण्डेय

प्रस्तावना – पश्चिमी राष्ट्रों में विकास प्रक्रिया में निजी और सरकारी क्षेत्रों का अद्भूत सम्मिलन हुआ है। विकासशील राष्ट्रों की विकास प्रक्रिया में सरकारी भूमिका का महत्व बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा आर्थिक विकास के नूतन क्षितिज प्राप्त किये जा सकते है। लोक–कल्याणकारी राज्य के अभ्युदय ने राज्य की भूमिका को विस्तृत कर दिया है। आर्थिक विकास में सरकारी भूमिका के बारे में अर्थशास्त्र भले ही एकमत नहीं, किंतु इस तथ्य पर सभी सहमत है कि आर्थिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है।

सरकारी क्रियाओं से आर्थिक विकास को तीव्र गति मिलती है। हरमन फाइनर के मतानुसार सरकार वांछनीय विधान, कानून और क्रियाविधियों को निश्चित करके, कुशल श्रम–शक्ति का निर्माण करके विनियोगकर्ताओं और नव–प्रर्वतकों को प्रभावित करके जनसंख्या साधनों को प्रभावित करके और विदेशी व्यापार पर प्रभाव डालकर, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार ही प्रत्यक्ष उपभोक्ता बचत करने वाले, बीमा करने वाले और गारंटी देने वाले उत्पादक, संसाधनों के स्वामी एवं नव–प्रवर्तक के रूप में काम करके आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकती है।

आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका –

(1) राष्ट्र के आर्थिक ढांचों की रक्षा करना –सरकार देश की आर्थिक जीवन को निश्चित करती है। सरकार ही इस बात का निर्णय करती है कि राष्ट्र के आर्थिक जीवन का ढांचा कैसा हो और उसको स्थायी किस प्रकार बनाया जाय। सरकार आर्थिक ढांचे के अनुरूप कानून की व्यवस्था करती है। इन कानूनों द्वारा सरकार देश की आर्थिक बाधाओं को दूर करती है। ये कानून सम्पत्ति क उत्तराधिकारों मालिकों और श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों, प्रसंविदा आदि के संबंधों से होते है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक जीवन की बाधाओं को समाप्त करना होता है।

(2) नियमन और नियंत्रण – सरकार का प्रमुख कार्य आर्थिक जीवन को नियमित करना है। वह श्रमिकों एवं मालिकों के संबंधों को इस प्रकार से नियमित करता है। जिससे मालिक श्रमिकों का शोषण नहीं कर सके। उपभोक्ताओं केंद्रित में वह एकाधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। सरकार मूल्यों की स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैकों और व्यापरियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है।

(3) वित्तीय सहायता – राज्य अथवा सरकार व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वह कृषकों,उद्योगपतियों और व्यापारियों को आवश्यक ऋण, सरंक्षण एवं परामर्श देती है। यह आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए विक्रेताओं उत्पादकों तथा बाजार पर नियंत्रण बनाए रखती है।

(4) सार्वजनिक हित – सरकार का एक अन्य प्रमुख कार्य सार्वजनिक वित्तीय कार्यों का सम्पादन करना है। देश में धन के वितरण में असमानताओं को दूर करके तथा अन्य आर्थिक एवं वित सम्बन्धी कार्य सरकार सम्पन्न करती है। वह व्यक्तियतयों से कर और ऋण के रूप में धन प्राप्त करती है तथा इस एकत्रित धन के जनसमुदाय के हित में व्यय करती है।

(5) पूर्ण रोजगार – संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने देशवासियों को पूर्ण रोजगार देने और व्यक्तियों के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि की व्यवस्था करे। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। अतः सरकार का दायित्व है कि वह अपने विकास कार्यों को इस प्रकार संतुलित करें कि देश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो। आज के विकासशील और विकसित सभी राष्ट्र अपने साधनों के अनुरूप इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना अपना कर्तव्य समझता है कि उनके नागरिकों को कार्य के अवसर प्राप्त हो।

(6) राजकोषीय नीति– शुल्क–नीति आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें सार्वजनिक राजस्व, व्यय ऋण कमजोर अर्थ प्रबन्धन आदि उन वित्तीय यंत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक क्रियाओं को वांछित दिशा में प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रयुदत किए जाते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से शुल्क नीति के निम्नांकित उद्देश्य है।

(1) उपभोग को नियंत्रित करके राष्ट्रीय आय में बचत क अनुपात को बढ़ाना।

(2) विनियोग की दर में वृद्धि करना और विनियोगों को उत्पादक कार्यों की ओर प्रवाहित करना।

(3) आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं में कमी करना।

(4) सरकार के हाथों में विनियोग के लिए पर्याप्त साधन जुटाना।

(7) विदेशी व्यापार नीति– आर्थिक विकास के लिए विदेशों से मशीन, औजार, कच्चा माल अन्य पूंजीगत सामान और तकनीकी विशेषज्ञों का आयात करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब देश के पास पर्याप्त मात्रा में विदेश विनिमय हो। अतः सरकार को इस प्रकार की आयात–निर्यात नीतियां अपनानी चाहिए जिससे निर्यातों में वृद्धि और अनावश्यक आयातों में कमी हो व्यापार संतुलन पक्ष में रहे और पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सके। किन्तु आयात–निर्यात करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण नहीं लगे, जिससे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचे। इसी प्रकार उन वस्तुओं के निर्यात को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। जिससे उनका देश में ही उपयोग करके आर्थिक प्रगति की जा सके।

(8) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – कोई भी देश दूसरे देश के सहयोग के बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। यद्यपि इस प्रकार का सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है। जब संबंधित देश के अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे हो। साथ ही उस देश की विकास परियोजनाएं भी व्यावहारिक और लाभप्रद हो। ऐसा होने पर ही दूसरे देश के विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसके विकास में रूचि लेंगे। स्पष्ट है कि विकासशील देशों की सरकारों की अन्य देशों के साथ अच्छे राजनीतिक

सम्बन्ध स्थापित करके सम्मानजनक शांतिपूर्ण समझौतों द्वारा विश्व के विकसित देशों से वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त करने चाहिए।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहयोग – सरकार ही राष्ट्र के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष तथा एशियाई बैंक इत्यादि वित्तीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है।

(10) नवीनतम वैज्ञानिक और तकनोकी आविष्कार और अनुसंधान – सरकार दारा देश के आर्थिक विकास के लिए नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार और अनुसंधान किये जाते है। सरकार आर्थिक विकास के लिए नवीनतम तकनीक को स्वीकार कर सकती है।

(11) सरकार की बहुमुखी भूमिका – राष्ट्र के विकास के लिए सरकार की बहुमुखी भूमिका होती है। जो निम्न है:–

(1) सरकार उपभोक्ता तथा वचनकर्ता के रूप में

(2) सुरक्षाकर्ता एवं उत्पादक के रूप में

(3) संसाधन धारक एवं नव–प्रवर्तक

(4) विकास का वातावरण

आर्थिक विकास में सरकार का योगदान कम हो या अथवा अधिक इसमें मतभेद है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित अर्थशास्त्री सरकार को विकास का पूरा उत्तरदायित्व सौंपना चाहते है जबकि उग्रवादी अर्थशास्त्री सरकार को प्रधान और निजी क्षेत्र को गौन स्थान देना चाहते हैं।

वर्तमान में विकासशील देशों के आर्थिक विकास मे ंतो सरकार को योगदान अनिवार्य है। अर्थशास्त्रियों का बहुमत है कि निम्नलिखित तत्वों के आधार पर आर्थिक विकास में सरकारी योगदान एवं हस्तक्षेप की मात्रा निश्चित करनी चाहिए।

(1) देश की सामाजिक एवं राजनैतिक विचारधारा।

(2) सरकार द्वारा साधनों को गतिशील बनाने की क्षमता और योग्यता

(3) सरकार की प्रशासनिक कुशलता और दृढ़ता

(4) सरकार द्वारा जनता को साथ लेकर चलने की क्षमता

(5) निजी उपक्रम व क्षेत्र

(6) वांछित विनियोगों की मात्रा और प्रगति

(7) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां।

संदर्भग्रंथ सूची :–

(1) डॉ. नीलिमा देशमुख 'आर्थिक नीति और प्रशासन' कालेज बुक डिपो त्रिपोलिया जयपुर 1997

(2) डॉ. धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन 'भारत की समाज' विवेक प्रकाशन दिल्ली 2005

(3) डॉ.ए.वी.भट्टाचार्य 'तुलनात्मक आर्थिक प्रणालियां

(4) अरूण कुमार 'जनजातीय विकास एवं पंचायती राज रावत् पब्लिकेशन्स जयपुर 2016

(5) बी.एस.भार्गव. पंचायती राज सिस्टम एण्ड पालिटिकल पार्टीज आशीष पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1975

(6) दीपक कुमार भार्गव 'मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम' एम.पी.ला पब्लिकेशन इंदौर 1981

(7) श्रीमती निर्मला बुच मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग प्रकाशन 1998

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM